

राष्ट्र संवाद

वर्ष 10, अंक : 51, 01 सितंबर से 07 सितंबर 2025, जमशेदपुर

आपका राष्ट्र, आपका संवाद : साप्ताहिक समाचार पत्र



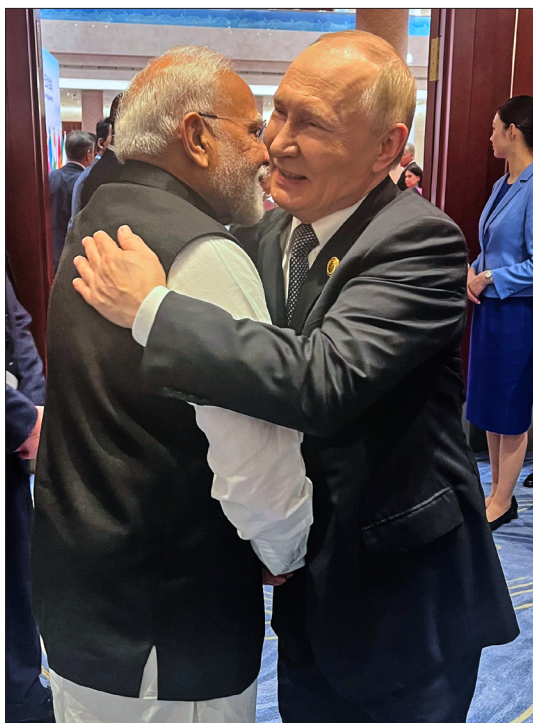
शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन संपन्न

3 शक्तियां भारत-चीन-रूस एक साथ

चीन के तियानजिन में आयोजित दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में विश्व की तीन शक्तियां एक साथ एक मंच पर दिखी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क के बीच हुए इस शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के रिश्तों में नयी गरमाहट आयी है। वहीं, रूस और भारत जो दशकों से एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं, की दोस्ती इस बार खुलकर नये रूप में दुनिया के सामने आयी है। भारत ट्रंप के शुल्क को गलत बताते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखे हुए है। वहीं, एससीओ के मंच से चीन ने भी परोक्ष रूप से यह संकेत दिया कि ट्रंप की दावागिरी अब नहीं चलेगी। इस मंच से भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो रूस-चीन के साथ ही एससीओ के लगभग सभी सदस्य देशों ने इसकी भर्त्सना की। इस पूरे सम्मेलन में पाकिस्तान मौजूद तो रहा, लेकिन उसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली।

पीएम मोदी ने सोमवार को एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पहलगांम में हुआ भयावह आतंकवादी हमला न केवल भारत की अंतरात्मा पर आघात है, बल्कि यह मानवता में विश्वास रखने वाले

प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक खुली चुनौती भी है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड त्यागने की जोरदार वकालत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वैश्विक नेताओं की उपस्थिति में मोदी ने वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई 'मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है'। पाकिस्तान और इसका (आतंकवाद का) समर्थन करने वालों को स्पष्ट संदेश देते हुए मोदी ने कहा, 'यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें कभी स्वीकार्य हो सकता है? हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। हमें मिलकर, हर रूप और अभिव्यक्ति में आतंकवाद का विरोध करना चाहिये। यह मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है।' पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इसके बाद एससीओ का साझा घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें पहलगांम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के इस रुख से सोमवार को सहमति जतायी गयी।



भारत-रूस संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के स्तंभ : मोदी



पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। भारत-रूस के संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के स्तंभ हैं। दोनों ने एससीओ सम्मेलन के इतर बैठक की, जिसमें आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोदी ने कहा, भारत

यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करता है। यूक्रेन संघर्ष को यथाशीघ्र समाप्त करना मानवता का आह्वान है। उम्मीद है, सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। पुतिन ने कहा, रूस और भारत ने दशकों से 'विशेष मैत्रीपूर्ण और विश्वास-आधारित' संबंध बनाये रखे हैं और यह संबंधों के भविष्य के विकास की नींव है।



देवानंद सिंह

मोदी-शी मुलाकात-अमेरिका का दबाव और भारत की कूटनीतिक दुविधा

भारत और चीन के रिश्तों की कहानी सिर्फ दो पड़ोसियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के वैश्विक शक्ति समीकरणों की कहानी भी है। रविवार को तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने-सामने मिले। सात साल बाद मोदी का चीन दौरा हुआ और 2018 के बाद यह पहली बार था जब दोनों नेता चीन की धरती पर एक-दूसरे से आमने-सामने बातचीत कर रहे थे। इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिकता या फोटो-ऑप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे गहरी कूटनीतिक गणनाएं, रणनीतिक मजबूरियां और अंतरराष्ट्रीय दबाव काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि पिछले साल कज़ान (रूस) में दोनों नेताओं की सार्थक चर्चा ने रिश्तों को सकारात्मक दिशा दी थी। उन्होंने सीमा पर डिस्इंगेजमेंट और शांति बहाली का जिफ्र किया और बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच सहमति को रेखांकित किया। वहीं शी जिनपिंग ने वैश्विक बदलावों का हवाला देते हुए कहा कि चीन और भारत, दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं के प्रतिनिधि और दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। उनके मुताबिक ड्रेगन और हाथी का साथ ग्लोबल साउथ और मानवता के लिए बेहद जरूरी है।

मुलाकात के दौरान चाहे जितनी भी सकारात्मक बातें कही गई हों, वास्तविकता यह है कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल नहीं हुई है। चीन अब भी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है और बार-बार उसका नामकरण करता रहा है। भारत “वन चाइना पॉलिसी” मानता है, लेकिन चीन वन इंडिया पॉलिसी मानने को तैयार नहीं दिखता। यही द्वंद्व इस रिश्ते का सबसे बड़ा बोझ है।

पिछले वर्षों में चीन ने न सिर्फ सीमा पर सैन्य उपस्थिति मजबूत की है, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहराया है। पाकिस्तान को रियल-टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराना हो या सीमा के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना चीन का हर कदम भारत के लिए सीधे सुरक्षा खतरे पैदा करता है। ऐसे में, यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या मोदी-शी मुलाकात वाकई रिश्तों में नया मोड़ लाएगी या यह केवल औपचारिक संवाद भर रह जाएगा?

इस मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण आयाम अमेरिका है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दो दशकों में मजबूत हुए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दबावपूर्ण रवैये ने हालात को जटिल बना दिया है। पूर्व अमेरिकी राजदूत माइकल मैकफॉल ने तो खुले शब्दों में कहा कि ट्रंप ने मोदी को इतना अलग-थलग कर दिया कि अब वह शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मंच साझा करने पर मजबूर हैं। यह टिप्पणी केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत-अमेरिका रिश्तों में असहजता बढ़ रही है।

भारत जानता है कि अमेरिका के बिना वह अपनी रणनीतिक कमियों को नहीं भर सकता। रक्षा तकनीक, ऊर्जा सहयोग, और इंडो-पैसिफिक रणनीति में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन अगर अमेरिका लगातार भारत

को दबाव में रखेगा, तो भारत को विकल्प तलाशने ही होंगे। चीन के साथ संवाद उसी विकल्प तलाशने का हिस्सा है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में दोनों देशों का व्यापार लगभग 127.7 अरब डॉलर तक पहुंचा। भारत ने अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में ही 48 अरब डॉलर का आयात चीन से किया। यह व्यापारिक असंतुलन भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत के उद्योगों की निर्भरता इतनी गहरी है कि अचानक दूरी बनाना संभव नहीं।

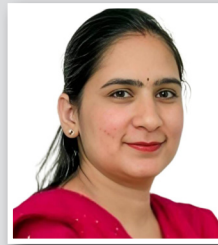
यही वह आर्थिक मजबूरी है जो राजनीतिक कड़वाहट के बावजूद दोनों देशों को बातचीत की मेज पर खींच लाती है। मोदी ने तियानजिन में कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट्स की बहाली का उल्लेख कर यह संदेश देने की कोशिश की कि लोग-से-लोग संपर्क अभी भी संबंधों की रीढ़ है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब चीन की रणनीतिक चालाकियों पर पर्दा डालने के लिए पर्याप्त है?

थिंक टैंक ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूशन की वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान का कहना है कि आज रूस और चीन के रिश्ते भारत से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि रूस पारंपरिक रूप से भारत का मित्र रहा है और उसका झुकाव हमेशा चीन-विरोधी ध्रुव पर रहा। लेकिन आज वही रूस, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से चीन पर निर्भर है।

भारत को यह भी समझना होगा कि रूस-चीन का गठजोड़ दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह संतुलन एक बेहद नाजुक रस्सी पर चलने जैसा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मोदी इस बार बहुत कमजोर स्थिति में चीन जा रहे हैं। अमेरिका से रिश्तों में दरार, सीमा पर चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान को लेकर चीन की अडिग स्थिति भारत को दबाव में डाल रही है। चीन ने न तो एलएसी पर कोई रियायत दी, न ही व्यापार या तिब्बत के मुद्दे पर।

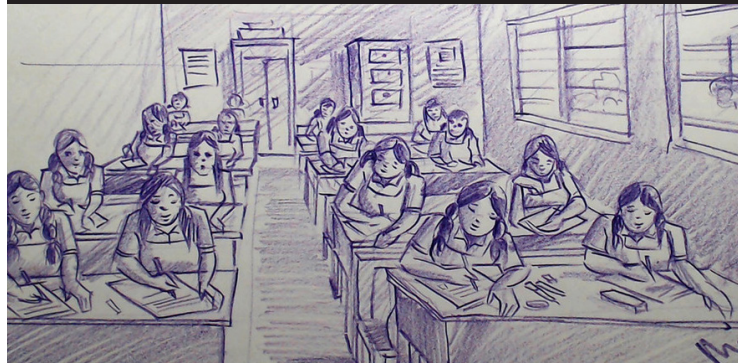
विशेषज्ञों के अनुसार पिछले अनुभव बताते हैं कि चीन भारतीय कमजोरी का फायदा उठाएगा, भरोसेमंद साथी बनने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब मोदी ने शुरुआती दिनों में चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, तो चीन ने उसी का फायदा उठाकर सीमा पर चुपचाप बढ़त बनाई। आज भी स्थिति अलग नहीं है। तियानजिन समिट में मोदी का सामना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी होना है। यह मुलाकात पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रही है। भारत-पाकिस्तान रिश्ते हमेशा से भारत-चीन समीकरणों से जुड़े रहे हैं। चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है और भारत जानता है कि जब तक चीन पाकिस्तान पर अपना हाथ रखेगा, दक्षिण एशिया में शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, कैसे अमेरिका, चीन और रूस के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना भी जोखिम भरा है और चीन से नाता तोड़ना भी अव्यावहारिक। यही कारण है कि मोदी का यह दौरा रणनीतिक संतुलन की तलाश का हिस्सा है।

“शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता”



डॉ. प्रियंका सौरभ

जब विद्यालय शिक्षण का केंद्र नहीं रहते, तो शिक्षा व्यापार बन जाती है



लगभग 3988 रुपये सालाना है। यह अंतर केवल आय स्तर का ही नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच की असमानता का भी द्योतक है। शहरों में कोचिंग उद्योग संगठित रूप में कार्य कर रहा है, जबकि गाँवों में यह अधिकतर व्यक्तिगत ट्यूशन तक ही सीमित है।

एक और गंभीर पहलू यह है कि शिक्षा पर यह अतिरिक्त बोझ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गहरे संकट में डाल देता है। उच्च वर्ग के बच्चे महंगी कोचिंग और ट्यूशन से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे इसी कारण पीछे छूट जाते हैं। यह शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप पर आघात है, क्योंकि शिक्षा समान अवसर प्रदान करने का माध्यम होनी चाहिए, न कि असमानता को और बढ़ाने का कारण। सरकार ने कई बार दावा किया है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कक्षा-कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है कि छात्र आत्मनिर्भर हो सकें। विद्यालयों को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने वाली प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित करना चाहिए।

कोचिंग पर निर्भरता एक और संकट खड़ा कर रही है — यह विद्यार्थियों को रटत संस्कृति की ओर धकेल रही है। कोचिंग संस्थान सामान्यतः परीक्षा परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, वहाँ सृजनात्मकता या जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। इस प्रकार विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने की मशीन बनते जा रहे हैं, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व का

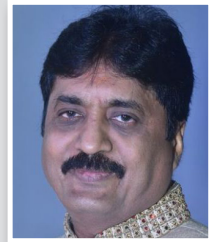
निर्माण कर रहे हैं।

समाधान के रूप में सबसे पहले विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षक पदों की रिक्तियाँ तत्काल भरी जानी चाहिए, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए और शिक्षण पद्धति को अधिक व्यावहारिक तथा छात्र-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। जब तक विद्यालयों में विश्वास नहीं बनेगा, तब तक कोचिंग का यह बाजार यूँ ही बढ़ता जाएगा।

यह भी आवश्यक है कि शिक्षा नीतियों में इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि कोचिंग का दबाव लगातार बढ़ता गया तो यह नीति भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज समय की मांग है कि शिक्षा का बोझ बच्चों से कम किया जाए। उन्हें कोचिंग संस्थानों की दीवारों के बीच कैद करने के बजाय खुले वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाए। प्रतिस्पर्धा की भावना अच्छी है, लेकिन जब यह केवल आर्थिक सामर्थ्य पर आधारित हो जाए तो यह समाज में गहरी खाई पैदा करती है।

शिक्षा का बाजार लगातार फैल रहा है और यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई, और अभिभावकों का विश्वास वापस लाया गया, तभी हम कोचिंग पर निर्भरता कम कर पाएँगे। अन्यथा, हर तीसरा नहीं बल्कि हर दूसरा बच्चा भी कोचिंग की ओर भागता नज़र आएगा।

प्रेम-भक्ति एवं शक्ति की अनंत ज्योति हैं राधाजी



ललित गर्ग

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति, शक्ति और समर्पण का अनोखा पर्व लेकर आता है—यह है राधाष्टमी। इसे राधा रानी का जन्मोत्सव माना जाता है। यह केवल किसी भक्ति की शिखर नारी चरित्र के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की अभ्यर्थना है जिसने स्वयं श्रीकृष्ण के जीवन को एक अनूठी ऊँचाई दी। इस दिन भक्त राधा और श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा से सुख-समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। ब्रजभूमि, खासकर बरसाना में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाजी प्रेम, भक्ति और श्रीकृष्ण के भीतर छिपी शक्ति का प्रतीक हैं; वह प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की देवी और श्रीकृष्ण की आंतरिक शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। उनका दिव्य प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की एक मिसाल है। यदि श्रीकृष्ण लीला, माधुर्य और करुणा के अवतार हैं, तो राधा उस लीला का रस, उस माधुर्य की गहराई और उस करुणा की आत्मा हैं। इसीलिए भारतीय भक्ति परंपरा में कहा गया—“राधे बिनु नहीं कृष्ण, कृष्ण बिनु नहीं राधे”।

राधा भारतीय संस्कृति में केवल एक स्त्री का नाम नहीं हैं, वे प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उनका प्रेम सांसारिक या देहाधारित नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम स्वार्थ और अधिकार से परे है, यह प्रेम केवल समर्पण और तादात्म्य का है। राधा का जीवन त्याग और अनुराग का अद्भुत समन्वय

है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उनका हर भाव, हर श्वास केवल श्रीकृष्ण में रमा रहा। यही कारण है कि भक्त कवियों ने राधा को ‘भक्ति-रस की मूर्ति’ और ‘प्रेम की अधिष्ठात्री देवी’ कहा। सूरदास ने लिखा—‘प्रेम भया मनु भाव समाना, राधा तन मन कृष्ण बखाना।’ अर्थात्, प्रेम ऐसा हो कि हृदय और आत्मा में केवल श्रीकृष्ण का ही वास हो जाए। निश्चित ही राधा और श्रीकृष्ण का संबंध, आत्मा और परमात्मा का अद्भुत एवं विलक्षण संवाद है। सामान्य दृष्टि से देखने पर राधा और श्रीकृष्ण का संबंध केवल प्रेमिका-प्रेमी का प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहन है। यह संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संवाद इसलिये है कि इसमें किसी प्रकार का मोह, स्वार्थ या वासना नहीं है। राधा श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती हैं। श्रीकृष्ण लीला के केंद्र हैं, परंतु वह लीला राधा के बिना अधूरी है। इसीलिए भक्त परंपरा में श्रीकृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है, “राधे-कृष्ण”, “श्यामा-श्याम”। यह क्रम अपने आप में गहरा दार्शनिक संदेश देता है कि परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग राधा जैसे प्रेम और भक्ति से होकर जाता है। राधा केवल श्रीकृष्ण की प्रेयसी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और प्रेरणा हैं। गीता में श्रीकृष्ण ने प्रकृति के दो रूप बताए हैं—अपरा और परा। राधा को ‘परा प्रकृति’ का स्वरूप माना जाता है, जो जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। वे श्रीकृष्ण की लीलाओं की आत्मा हैं, उनकी

आराधना का आधार हैं। राधा के प्रेम में कोई अधिकार

नहीं, केवल समर्पण है। उनका संदेश है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। यही देने की भावना जीवन को ऊँचाई देती है। यह प्रेम केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों में ही नहीं, बल्कि मनुष्य और ईश्वर के संबंध में भी उतना ही प्रासंगिक है।

राधा की भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। उनका प्रेम निष्काम है, केवल श्रीकृष्णमय है। उन्होंने अपने अस्तित्व को ही श्रीकृष्ण में विलीन कर दिया। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ने राधा की भक्ति को अपनाया और उसी रस में डूबकर कहा—‘मैं राधा की भक्ति में श्रीकृष्ण को देखता हूँ और श्रीकृष्ण की भक्ति में राधा को।’ सूरदास, रसखान, विद्यापति, मीराबाई—सभी भक्त कवियों ने राधा के माध्यम से ही प्रेम और भक्ति के गहनतम स्वरूप का चित्रण किया। मीराबाई ने जब कहा—‘मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई’—तो उसमें राधा का ही भाव प्रतिध्वनित होता है। आज के समय में जब संबंधों में स्वार्थ, गणना और तात्कालिकता का समावेश बढ़ता जा रहा है, तब राधा का चरित्र हमारे लिए नई रोशनी देता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण, विश्वास और त्याग हो। समकालीन जीवन में जहाँ परिवार और समाज टूटते जा रहे हैं, वहाँ राधा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो उठता है।



अफगानिस्तान में भूकंप, 1450 की मौत

काबुल : अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में 622 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। अफगानिस्तान में आए भूकंप पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को गहरी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए भूकंप पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हरसंभव सहायता मुहैया कराएगा। विनाशकारी भूकंप में हुए नुकसान की जानकारी सोमवार को सरकारी रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ अफगानिस्तान (आरटीए) ने दी। आपदा के बाद बचाव दल राहत कार्य में जुटा है। दूरदराज के इलाकों में नुकसान का आकलन कर मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने आरटीए के हवाले से बताया कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 अगस्त को स्थानीय समयानुसार रात 11:47 बजे अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 27 किलोमीटर दूर और आठ किलोमीटर की गहराई पर था। अफगानिस्तान भूकंप के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यह कई फॉल्ट लाइनों के ऊपर स्थित है। यहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटें मिलती हैं। पूर्वी अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका भूस्खलन के लिए भी संवेदनशील है, जिससे आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल पश्चिमी भाग में आए भूकंपों में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले, 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने अनुमान लगाया था कि इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 4,000 लोग मारे गए थे। यह हाल के दिनों में आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में अफगानिस्तान में भूकंपों में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भूकंप से हर साल औसतन 560 मौतें होती हैं। मई 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान के तखर और बदखशां प्रांतों में आए भूकंप में लगभग 4,000 लोग मारे गए थे। उस समय करीब 100 गांव और 16,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दौरान 45,000 लोग बेघर हो गए थे।

एस. जयशंकर ने हरसंभव मदद का दिया आश्वासन



गहरे संकटो, सीमित संसाधनों से जूझ रहे देश के लिए समर्थन की अपील

अफगानिस्तान पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा है. ऐसे में यह आपदा पहले से जारी मानवतावादी प्रयासों को किस तरह से प्रभावित करेगी, विशेष रूप से जब जरूरतें पहले से ही बहुत हैं और आपके पास सीमित रकम है? ऐमी मार्टिन : तो यह एक संकट के भीतर एक और संकट है. हमें सूखा झेलना पड़ रहा है, जिससे उत्तरी प्रान्त पीड़ित थे मगर अब अब यह मध्य अफगानिस्तान के क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर रहा है. इस सिलसिले में प्रयास पहले से चल रहे हैं. हमने सूखे के विरुद्ध पूर्वानुमान पर आधारित कार्रवाई के लिए सहायता धनराशि जुटाई है, और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक अन्य अनुदान भी है. लेकिन फिर सूखे का पैटर्न भी बदल रहा है. और दूसरी बड़ी चुनौती है, वापिस लौटने वाली आबादी. पाकिस्तान और ईरान से जो लोग लौट रहे हैं, उन्हें फिर से अफगानिस्तान में समाहित करना, उनकी मदद करना और उनके लिए आजीविका के अवसर सृजित करना एक बड़ी चुनौती होगी. तो यह कई चुनौतियों का मिश्रण है.



सहायताकर्मी दुर्गम इलाकों में पैदल पहुंचा रहे मदद

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए भूकम्प से हुई बर्बादी के बाद विशाल स्तर पर आवश्यकताएं उपजी हैं और यूएन सहायता टीम प्रभावित समुदायों तक राहत पहुंचाने में जुटी हैं। अवरुद्ध सड़कों और टूटी हुई संचार लाइनों के बीच राहतकर्मी पैदल चलकर दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ लोगों को सबसे अधिक मदद की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र की आकलन टीमों ने मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, गाज़ी आबाद ज़िले की स्थिति का जायज़ा लिया। उनकी रिपोर्ट में मानवीय सहायता अभियान में तत्काल तेज़ी लाने पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के सलाम अल-जाबानी ने काबुल से जानकारी देते हुए कहा, “सबसे ज़रूरी है मलबे में दबे लोगों को निकालना। लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मृतकों को दफ़नाने और मलबे में फँसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकें।”

अफ़ग़ानिस्तान के सत्तारूढ़ प्रशासन की आरम्भिक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार देर रात पूर्वोत्तर क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.0 की तीव्रता वाले भूकम्प से कम से कम 1,400 लोगों की मौत हुई और 3,100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, चूँकि राहत और बचाव दल अब तक कई प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुँच सके हैं। चट्टानों, भूस्खलन और टूटी सड़कों की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें भूकम्प और उससे पहले हुई भारी बारिश ने और भी गम्भीर बना दिया है। अल-जाबानी ने बताया, “हमारी टीमों को गाड़ियाँ छोड़कर दो घंटे पैदल चलकर गाज़ी आबाद पहुँचना पड़ा। अन्य गाँव छह से सात घंटे की पैदल दूरी पर हैं और वहाँ अब तक कोई नहीं पहुँच सका है यहाँ तक कि स्थानीय अधिकारियों के हेलीकॉप्टर भी नहीं।” संचार व्यवस्था बेहद कमज़ोर है या लगभग पूरी तरह ठप पड़ी है। अल-जाबानी ने बताया, “एक स्वास्थ्य केन्द्र के पास केवल एक मोबाइल टावर काम कर रहा है, इसके अलावा पूरा इलाका संचार से कट चुका है।” विशाल



आवश्यकताएँ संयुक्त राष्ट्र ने सहायता प्रयासों के तहत प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 25 आकलन टीमों को भेजा है और काबुल से मानवतावादी सेवा की उड़ानें भी बढ़ाई हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) काबुल में मौजूद अपने भंडार से आवश्यक राहत सामग्री पहुँचा रही है,

जिनमें तम्बू, कम्बल और सोलर लैम्प शामिल हैं। तत्काल प्राथमिक ज़रूरतों में आपात आश्रय, दवाएँ, पीने का पानी और आपात खाद्य सहायता शामिल हैं। यूनीसेफ़ (UNICEF) के सलाम अल-जाबानी ने बताया, “दवाइयाँ पहुँचाना बेहद मुश्किल हो गया है ज़रूरी सामान केवल

पैदल ही लाया जा रहा है और वह भी पास के यूनीसेफ़ समर्थित अस्पताल से।” उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद नाज़ुक हालात में हैं। गाज़ी आबाद के एक क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केन्द्र की दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं। वहाँ डॉक्टर अब मरीजों का इलाज बाहर, पेड़ों के नीचे कर रहे

हैं, क्योंकि लोगों को अन्दर रहने में डर लग रहा है। बताया गया है कि हजारों स्थानीय लोग पानी और खाना लेकर प्रभावित इलाकों में पहुँच रहे हैं ताकि खोज एवं बचाव कार्यों में मदद कर सकें। यूनीसेफ़ अधिकारी ने बताया, “हजारों लोग लगातार इस क्षेत्र में आ-जा रहे हैं।”

धराली में हर तरफ तबाही, दो शव बरामद, 11 जवान लापता

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के बादग्रस्त धराली में बादल फटने के कहर के बाद बुधवार को हर तरफ मलबा और तबाही का मंजर है। भारी बारिश के बीच आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव व राहत अभियान जारी है। बचाव दलों ने बुधवार को जमा मलबे से दो शव बरामद कर लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बादग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायज़ा लिया। पीएम मोदी ने भी फोन पर उनसे बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। पीएम ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। बादल फटने की घटना में चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे बचाव अभियान में 190 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंगोत्री धाम में लगभग 400 यात्री हैं, जो सुरक्षित हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारे लिए एक-एक जान कीमती है। बाढ़ में 15 से अधिक लोग लापता हो सकते हैं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि लापता लोगों में 11 सैनिक भी शामिल हैं। उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे नदियाँ और नाले उफान पर हैं। हरिद्वार में गंगा 294 मीटर के अपने खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

नदियाँ उफनायीं, बाढ़ का खतरा : केंद्रीय जल आयोग ने देश के कई राज्यों में नदियों के जलस्तर में खतरनाक वृद्धि का बुलेटिन जारी किया। इसके अनुसार, असम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है।



हिमाचल में भारी बारिश बचाये गये 413 तीर्थयात्री

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने से किन्नौर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया गया और 413 फंसे हुए श्रद्धालुओं को बचाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण तंगलिप्पी और कांग्रंग में दो अस्थायी पुल बह जाने के बाद श्रद्धालु फंस गये थे। आइटीबीपी ने एक्स पर बचाव कार्यों के वीडियो साझा किये, जिनमें श्रद्धालु नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जपलाइन के जरिये जाते देखे जा सकते हैं।





पंजाब जलमग्न

भारी बारिश से जालंधर में बाढ़ से बिगड़े हालात, स्कूल बंद, हेल्पलाइन नंबर जारी

जालंधर। पंजाब के जालंधर जिले में भारी बारिश ने हालात को गंभीर कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण जालंधर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन, मॉडल टाउन, अर्बन एस्टेट फेस-1 और फेस-2 और किशनपुरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

जालंधर में दोमोरिया पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पंजाब सरकार ने आठ जिलों के बाढ़ अब जालंधर को भी बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में बनाने की अपील की है, लेकिन सरकारी बुलेटिन में जालंधर को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने से लोगों में भय और असमंजस की स्थिति है।

पंजाब के जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला, मोगा और गुरदासपुर सहित नौ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र का जट्टा गांव रावी नदी में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, जहां घरों में तीन से साढ़े चार फीट

तक पानी भर गया है। जालंधर के शहरी इलाकों में भी सड़कों और घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

भाखड़ा और रणजीत सागर डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज, ब्यास, और रावी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। जालंधर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन नंबर: 0181-2224417) स्थापित किया गया है। सरकार ने स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने के आदेश दिए हैं।

वहीं, इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर के गांव मियानी में राहत कैप का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दौरे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "होशियारपुर के गांव मियानी में राहत कैप का दौरा किया। लोगों का हाल-चाल जाना और उन्हें दी जा रही राहत सामग्री का जायजा लिया। साथ ही बातचीत करके यह सुनिश्चित किया कि जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहेगी। हमारी सरकार हर पहलू से लोगों के साथ खड़ी है।"

बाढ़ से पांच लाख एकड़ रकबा डूबने से देश का अन्न भंडार संकट में, आर्थिक सहायता मांगी

चंडीगढ़। बाढ़ के कारण कठिन दौर से गुजर रहे देश के अन्न भंडार पंजाब के लिए, आज राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और बड़ा विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे चार लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की।

स. खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर पड़े गंभीर असर को उजागर किया। अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के उपरांत स. खुड्डियां ने चौहान का स्वागत किया, जो बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित किसानों से मिलने के लिए राज्य के दौर पर

आए थे।

बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान को उजागर करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी की चपेट में आई हैं। कटाई के सीजन से कुछ सप्ताह पहले, धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस तबाही के नतीजे स्वरूप किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। पशुधन को हुए नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर पड़ा है।

स. खुड्डियां ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का विशेष योगदान है और एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते पंजाब केंद्रीय खाद्य पुल में अहम योगदान देता है। हालांकि बाढ़ के कारण फसलें, कृषि बुनियादी ढांचा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली

कृषि पर भारी दबाव है, इसलिए इस क्षेत्र को फिर से जीवित करने और किसानों को तत्काल सहायता देने की आवश्यकता है।

बाढ़ पीड़ितों के लिए नगण्य मुआवजे पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का मौजूदा मुआवजा 6,800 रुपये प्रति एकड़ है, जो कि किसानों के वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुआवजे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए।

स. खुड्डियां ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) के 8,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।

जालंधर में भारी बारिश के चलते दुकानदारों को लाखों का नुकसान, करंट लगने से रेलकर्मों की मौत

पंजाब में हो रही लगातार बारिश के चलते जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जालंधर शहर में मूसलाधार बारिश के बाद दुकानों और घरों के अंदर पानी भर गया। जालंधर के रिहायशी इलाके मॉडल टाउन में भी जलभराव हो गया है। मॉडल टाउन की कई कर्मशियल बिल्डिंग में पानी पहुंच गया है, जिस वजह से वहां पर अपना कारोबार कर रहे लोगों को लाखों का नुकसान हो गया है।

जालंधर में ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें तीन घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, सुबह एक रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जालंधर की मॉडल मार्केट जलमग्न हो गई है। बारिश के चलते मार्केट की दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो गया। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि प्रशासन को समय रहते सारे इंतजाम कर लेने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन इसमें विफल रहा है। हालांकि, अब प्रशासन पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। लोगों को हुए भारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब प्रशासन नहीं दे रहा। रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। यहां 90 प्रतिशत तक सीवरेज ब्लॉक हैं, ऐसे में जलभराव स्वाभाविक है।

इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य के लिए राहत की मांग की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब के लिए मुश्किल समय है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब का 60,000 करोड़ रुपये का रुका हुआ फंड जारी करे।

मुख्यमंत्री मान ने पत्र में लिखा था कि पंजाब इस समय दशकों की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक से जूझ रहा है, जिसका असर लगभग 1,000 गांवों और लाखों लोगों पर पड़ा है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 7 जिलों गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर में भीषण बाढ़ आ गई है। स्थिति बिगड़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ज्यादा बिगड़ने की आशंका है।



पाकिस्तान में बाढ़ से 883 लोगों की मौत, इस्लामाबाद में बाढ़ की चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जून के अंत से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है। इस मानसूनी बारिश में हुए हादसों में अब तक 883 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,200 घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात से बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो और बच्चों की जान चली गई। इनमें से एक की मौत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और दूसरे की जान इस्लामाबाद में गई। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने चेतावनी दी है कि ऊपरी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बुधवार को अपने राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (एनईओसी) के माध्यम से अगले 12 से 24 घंटों में पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में संभावित बारिश की चेतावनी जारी की थी। खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) और पंजाब प्रांतों को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। केपी में 488 लोगों की मौत हो गई है और 360 घायल हुए हैं। सिंध में 58, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में 41, पीओके में 38, बलूचिस्तान में 26 और इस्लामाबाद में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पीएमडी ने चेतावनी दी है कि पंजाब के गंदा सिंह वाला क्षेत्र में सतलुज नदी में बाढ़ का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा बना रहेगा, जबकि चिनाब नदी में एक नई बाढ़ पंजाब के मराला से नीचे की ओर पहुंच सकती है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजनद नदी (जहां चिनाब, रावी और सतलुज नदियां मिलती हैं) में 4 और 5 सितंबर के बीच जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि और सैकड़ों गांवों को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सिंध प्रांत के गुड्डु में सिंधु नदी में भी 6 या 7 सितंबर तक बाढ़ खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका है। पीएमडी के अधिकारियों ने पंजाब, केपी, पीओजीबी और पीओके के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है।

चित्राल, दीर, स्वात, बुनेर और एबटाबाद सहित केपी के विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने निचले इलाकों में बाढ़ की भी चेतावनी दी है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के उफान पर होने और भूस्खलन का खतरा भी है। पीडीएमए के अनुसार, चिनाब नदी से आई बाढ़ ने पंजाब के झांग में 261 गांवों और मुजफ्फरगढ़ में कम से कम 24 गांवों को जलमग्न कर दिया है। बाढ़ में पानी के प्रचंड बहाव ने 9,200 से ज्यादा घरों को भी नष्ट कर दिया है, जिनमें से 4,700 केपी में और 2,100 पीओके में हैं। 6,000 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। इस आपदा में पूरे पाकिस्तान में लगभग 240 पुलों और 670 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचाया है।





टाटा स्टील के कर्मचारियों में बंटेंगे ₹303.13 करोड़ बोनस, अधिकतम मिलेंगे ₹3.92 लाख

टाटा स्टील में गुरुवार को बोनस समझौता हुआ। कर्मचारियों को 16.69% बोनस मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों में कुल 303.13 करोड़ रुपये का वितरण होगा। टाटा स्टील के कुल 25,907 कर्मचारियों में बोनस राशि बांटी जायेगी। टाटा स्टील जमशेदपुर (ट्यूब शामिल) के कुल 11,446 कर्मचारियों को 152.44 करोड़ रुपये बोनस की राशि मिलेगी। औसत बोनस राशि 1,33,178 रुपये है। ओल्ड सीरीज ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 3,92,213 रुपये मिलेंगे, जबकि 2024 में अधिकतम 4,09,462 रुपये मिले थे। वहीं, एनएस ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 1,10,547 रुपये और न्यूनतम 39,004 रुपये मिलेंगे, जबकि बीते वर्ष अधिकतम 1,13,515 रुपये और न्यूनतम 38,203 रुपये मिले थे। त्रिपक्षीय बोनस समझौता में सरकार की तरफ से उप श्रमायुक्त अरविंद कुमार मौजूद रहे। मैनेजमेंट की ओर से एमडी सह सीइओ टीवी नरेंद्रन, चीफ पीपुल ऑफिसर अतरई सान्याल, वीपी सीएस डीबी सुंदर रामम, वीपी चैतन्य भानु, वीपी पीयूष गुप्ता, वीपी प्रोबाल घोष, वीपी अक्षय खुल्लर, वीपी फाइनांस संदीप भट्टाचार्य, सीएचआरओ जमशेदपुर जुबिन पालिया और टाटा वर्कर्स यूनियन की तरफ से अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु, महामंत्री सतीश सिंह, उपाध्यक्ष शहनवाज आलम समेत अन्य मौजूद रहे।

₹30.30 करोड़ बोनस मद में अतिरिक्त मिले : जानकारी के अनुसार, बोनस मद में 272.83 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन टाटा स्टील के एमडी सह सीइओ टीवी नरेंद्रन, चीफ पीपुल ऑफिसर अतरई सान्याल और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु के बीच बातचीत में तय किया गया कि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए राशि बढ़ाई जाये। इसके बाद प्रबंधन ने बोनस मद में 30.30 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये। जिससे बोनस की राशि पिछले साल की तरह 303.13 करोड़ रुपये हो गयी। यह राशि बेसिक और डीए का 16.69 फीसदी है।

टाटा टिनप्लेट में 4.02 करोड़ रुपये बांटे जायेंगे। टाटा स्टील टिनप्लेट डिवीजन में भी गुरुवार को 16.69 प्रतिशत बोनस समझौता हुआ। इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 75,075 रुपये और न्यूनतम 30,581 रुपये मिलेंगे। इस वर्ष कंपनी के 844 कर्मचारियों के बीच लगभग 4.02 करोड़ रुपये बांटे जायेंगे।



- ◆ एनएस ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 1.10 लाख व न्यूनतम 39,004 रुपये मिलेंगे
- ◆ 16.69% बोनस पर प्रबंधन और यूनियन सहमत, 25907 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- ◆ न्यूनतम 39,004 रुपये औसत ₹1.33 लाख मिलेंगे



बोनस समझौता के बाद टाटा स्टील के एमडी सह सीइओ टीवी नरेंद्रन व अन्य .

टाटा स्टील वायर डिवीजन में ₹2 करोड़ बोनस

जमशेदपुर. टाटा स्टील वायर डिवीजन (पुराना नाम तार कंपनी जेम्को) में भी गुरुवार को बोनस समझौता हुआ। कंपनी के 422 कर्मचारियों के बीच 2 करोड़ रुपये का वितरण होगा। कर्मचारियों को अधिकतम 79,099 रुपये और न्यूनतम 30,581 रुपये मिलेंगे। वर्ष 2024 में 460 कर्मचारियों के बीच 2 करोड़ 22 लाख रुपये बोनस की राशि का वितरण हुआ था। कर्मचारियों को न्यूनतम 16,500 रुपये और अधिकतम 64,500 रुपये मिले थे। बोनस समझौते पर मैनेजमेंट की ओर से चीफ पीपुल ऑफिसर अतरई सान्याल, सीएचआरओ इंडिया मैनुफैक्चरिंग जुबिन पालिया, चीफ एचआरबीपी किंकीनी दास, चीफ आइआर राहुल दुबे, उत्कर्ष भारद्वाज और टाटा वायर इंप्लाईज यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, उपाध्यक्ष श्रीकांत सिंह और अन्य मौजूद रहे।

इन्हें मिलेगा बोनस

टाटा स्टील के जमशेदपुर मुख्य प्लांट, ट्यूब डिवीजन, कलिंगानगर, जामाडोबा माईस, वेस्ट बोकारो माईस, नोवामुंडी माईस, टिनप्लेट, टिस्को ग्रोथ शॉप, आइएसडब्ल्यूपी, मार्केटिंग एंड सेल्स के कर्मचारियों में बोनस की राशि बंटेंगी।

टीजीएस के 230 कर्मचारियों में बंटेंगे ₹2.44 करोड़

जमशेदपुर. टाटा स्टील के गम्हरिया स्थित टिस्को ग्रोथ शॉप (टीजीएस) में भी बोनस समझौता हुआ। इसके तहत तय किया गया कि कर्मचारियों को इस साल टीजीएस में कुल 230 कर्मचारियों (पिछली बार 237 थे) को बोनस की राशि दी जायेगी। बोनस के मद में कर्मचारियों को 2.44 करोड़ रुपये (पिछले साल 2.80 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जायेगा। वहीं, इस दौरान कर्मचारियों को अधिकतम 3 लाख 26 हजार 691 रुपये (पिछले साल 3 लाख 35 हजार 458 रुपये मिला था) और न्यूनतम 3,26,691 रुपये (पिछले साल 70 हजार 785 रुपये मिला था) दिया जायेगा। बोनस समझौता पर टाटा स्टील की चीफ पीपुल ऑफिसर अत्रेयी, वीपी इंजीनियरिंग अक्षय खुल्लर, सीएचआरओ इंडिया जुबिन पालिया, चीफ आइआर राहुल दुबे व अन्य मौजूद रहे।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

समझौते के तहत 303.13 करोड़ रुपये बोनस राशि में मेरामंडली और एनआइएनएल के कर्मचारियों को हिस्सा नहीं दिया जायेगा। टीएसटीएल या टीएसटीएस जैसी सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों को भी इसमें से राशि नहीं दी जायेगी।

पश्चाताप की आग में जल रहे ट्रंप!



अभी तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पश्चाताप की आग में झुलसने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यूथ पर लिखा कि मुझे लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों देश अब चीन की राह पर निकल पड़े हैं। ट्रंप का यह बयान काफी कुछ बयां करता है। उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि भारत को खोने का डर उन्हें सताने लगा है। आखिर यह नौबत क्यों आई है और ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उससे दूर जा रहा है। ट्रंप की इस विडंबना से पहले यह बात करते हैं कि कैसे उन्होंने खुद भारत के रास्ते में कांटे बिछाए और उसे रास्ता बदलने पर मजबूर किया। जनवरी से पहले की बात करें तो भारत और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का ही सपोर्ट किया था। चुनाव के दौरान भारत में कई जगहों पर लोगों ने हवन और यज्ञ भी किया था। उम्मीद थी कि ट्रंप की जीत के बाद भारत के लिए अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन, 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के तत्काल बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ भारत पर ही 50 फीसदी का टैरिफ लगाया।

भारत ने क्यों बदला अपना रास्ता : अमेरिका ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही और 7 अगस्त से इसे लागू भी कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड डील को भी बेवजह की शर्तें लगाकर जानबूझकर अटकाया गया। अमेरिका को अच्छी तरह पता था कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट को कभी स्वीकार नहीं करेगा, बावजूद इसके वह इसी बात पर अटका रहा कि जब तक भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा, उससे ट्रेड डील नहीं की जाएगी। इस तरह, डील को बीच में ही अटकाकर 7

अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया। इतने के बाद भी ट्रंप का मन नहीं भरा तो रूस का साथ देने का आरोप लगाते हुए 27 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ और लगा दिया। यह किसी भी देश पर लगे टैरिफ से कहीं ज्यादा है।

ट्रंप को क्यों लगा कि जा रहा भारत : अब जबकि अमेरिका खासकर ट्रंप ने भारत के साथ कोई मुरौव्वत नहीं बरती और उस पर बेवजह टैरिफ लगा दिया तो भारत को अपने विकल्प तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं था। भारत दो ऐसे बड़े संगठन का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका नहीं शामिल है और इन दोनों ही संगठनों में रूस व चीन शामिल रहा। इससे पहले 2025 की शुरुआत से ही चीन ने भारत को कई जरूरी केमिकल और कच्चे माल की आपूर्ति रोक दी थी, तब उसे अमेरिका से उम्मीद थी। अमेरिका से भी परेशानी आने पर भारत को मजबूरन वापस चीन की तरफ जाना पड़ा।

ट्रंप को चुन गया पीएम मोदी का चीन दौरा : डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने भारत को वापस रेयर अर्थ और अन्य जरूरी उपकरणों व केमिकल की सप्लाई शुरू कर दी। भारत ने भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना ही मुनासिब समझा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 5 साल बाद चीन का दौरा किया और हाल में संपन्न एससीओ सम्मेलन में मोदी ने रूस व चीन के साथ भी शामिल था। समिट के एक साझा पत्र में भी शामिल था।

जिसमें सदस्य देशों की बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने और डॉलर से दूरी बनाने पर भी सहमति बनी। **ब्रिक्स सम्मेलन से ही लग गया था झटका :** चीन में हुई एससीओ समिट से पहले ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी जब जिनपिंग, मोदी और पुतिन एक मंच पर आए थे, तब भी ट्रंप को मिर्ची लगी थी। उन्होंने खुले मंच से कहा था अगर इन

देशों ने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। अब जबकि भारत ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित मात्रा में मजबूत करना शुरू कर दिया तो ट्रंप को लग गया कि शायद भारत उससे दूर जा रहा है।

ऐपल ने भी दिया दो टूक जवाब : ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में तमाम टेक दिग्गजों के साथ रात्रिभोज का आयोजन किया। इसमें सुंदर पिचाई और सत्या नडेला के साथ ऐपल के सीईओ टिम कुक भी शामिल थे। इस दौरान ट्रंप ने कुक से पूछा कि आप अमेरिका में कितना निवेश करेंगे तो उन्होंने कहा कि 600 अरब डॉलर। फिर पूछा कि भारत को लेकर क्या प्लान है। यहां ट्रंप यह सुनना चाहते थे कि ऐपल अपना कारोबार भारत में समेटेगा, लेकिन कुक ने जवाब दिया कि वह अपने कुल उत्पादन का 25 फीसदी भारत में ही करना चाहता है। यह एक तरह से ट्रंप के लिए झटका था और भारत के साथ अमेरिकी कंपनियों के जुड़ने की मजबूरी भी।

भारत पर टैरिफ लगा घर में भी घिरे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लगाने के फैसले ने न सिर्फ भारत-अमेरिका व्यापार समीकरण को हिला दिया है, बल्कि अमेरिका के भीतर ही राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों और मीडिया का कहना है कि यह कदम भारत-अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों को कमजोर कर सकता है, जिन्हें एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम माना जाता है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुआ और इससे वस्त्र, रत्न-आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, रसायन और मशीनरी जैसे बड़े क्षेत्रों को सीधा झटका लगा। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह कार्रवाई भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल की खरीद के कारण की गयी है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि चीन जैसे बड़े आयातकों को क्यों बख्शा गया। अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत पर टैरिफ, यूक्रेन की समस्या से बिलकुल भी जुड़ा नहीं लगता। अमेरिका को उन देशों पर ध्यान देना चाहिए जो बड़ी मात्रा में रूस का तेल खरीदते हैं, लेकिन इसके बजाय ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। इससे अमेरिका के आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है और भारत के साथ संबंध भी बिगड़ रहे हैं।

'लगता है हमने भारत-रूस को खो दिया', टैरिफ थोपने के बाद ट्रंप ने बयां किया दर्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा हुआ है और भारत, रूस और चीन एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'ऐसा लगता है कि हमने हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो।' चीन के तियानजीन शहर में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, व्लादिमिर पुतिन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। पीएम मोदी, पुतिन और चिनफिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर इस बैठक में थी। उनका बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और अमेरिका के संबंध अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत अपने पुराने दोस्त रूस के ज्यादा करीब दिख रहा है।

दिल्ली में घाट डूबे, निचले इलाकों में भरा पानी

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 206.83 मीटर तक पहुंचा, हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और लोहा पुल पर यातायात बंद कर दिया। दिल्ली में यमुना नदी के उफान ने एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। मंगलवार सुबह हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके आज दिल्ली पहुंचने से हालात और गंभीर हो सकते हैं। आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, देर रात 11 बजे जलस्तर 206.45 मीटर को पार कर गया था।

दिल्ली से नोएडा तक हजारों लोग प्रभावित : यमुना बाजार, बुराड़ी, एमनेस्टी मार्केट, तिब्बती बाजार, बासुदेव घाट और आईटीओ का छठ घाट जैसे इलाके पानी में डूब गए हैं। यमुना खादर, यमुना वाटिका और आसिता जैसे रिवर फ्रंट पार्क भी जलमग्न हो चुके हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 1,000 अवैध फार्महाउस पानी में डूब गए, जबकि जेवर के हजारों बीघा



खेतों को फसलें बर्बाद हो गईं। प्रशासन ने नदी किनारे की झुगियों को खाली करवाया और करीब 4,500 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। मयूर विहार, गीता कॉलोनी और पल्ला जैसे क्षेत्रों में टेंट लगाकर लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

लोहा पुल बंद, ट्रैफिक डायवर्जन : उफनती यमुना के कारण दिल्ली पुलिस ने पुराना लोहा पुल मंगलवार शाम 4 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिया है। ट्रैफिक को हनुमान सेतु, राजा

राम कोहली मार्ग और गीता कॉलोनी रोड की ओर डायवर्ट किया गया है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और लाल किला से आने वाले वाहनों को बाहरी रिंग रोड लूप से डायवर्ट किया जा रहा है, जबकि शाहदरा, सीलमपुर और शास्त्री पार्क से आने वाले वाहनों को पुश्ता रोड से रिंग रोड की ओर भेजा जा रहा है। पूर्वी दिल्ली से आने वाले वाहनों को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर और शांति वन चौक की ओर डायवर्ट किया गया है।

राष्ट्र संवाद

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

Website : www.rashtrasamvad.com • RNI No. : JAHIN/2014/63781

संपादक	: देवानंद सिंह
प्रबंधक संपादक	: रश्मि सिंह
कार्यकारी संपादक	: विजय शंकर मिश्रा
समन्वयक संपादक	: रत्नेश कुमार, अमन कुमार
महाप्रबंधक	: धीरज कुमार सिंह
प्रभारी बिहार, झारखंड	: निजाम खान
बिहार ब्यूरो प्रमुख	: चन्दन कुमार शर्मा
विशेष संवाददाता	: प्रकाश सिंह, जितेन्द्र शर्मा, जेपी सिंह

□ राष्ट्र संवाद में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार सुरक्षित। लेखकों के मतों एवं कथनों के लिए संपादक व प्रकाशक की अनुमति अनिवार्य नहीं। सभी विवादों का निपटारा जमशेदपुर न्यायिक क्षेत्र में ही किया जायेगा। छायाचित्र एवं अन्य सामग्रियां भी अन्य पत्र-पत्रिकाओं से साभार।

□ स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक देवानंद सिंह द्वारा चंद्र प्रेस, 63 पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 से मुद्रित तथा अमन पब्लिकेशन राष्ट्र संवाद, 66 गोलमुरी बाजार, जमशेदपुर - 3 से प्रकाशित।

□ फोन : 0657-2341060

□ मोबाइल : 09431179542/09334823893/07739802044